खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा धन-राशि की मांग

1556. **श्री वीरेन जे० शाह :**
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खादी और ग्रामोद्योग के विकास और संचालन के लिए 8,000 करोड़ रुपये की मांग की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या आयोग ने खादी उद्योग के विकास के लिए कोई विस्तृत योजना तैयार की है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस योजना के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित समयबद्ध लक्ष्य क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) :

(क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान खादी तथा ग्रामोद्योग के विकास के लिए 6,300 करोड़ रु० की मांग की है।

(ख) से (घ) सरकार का प्रयास खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग तथा उसकी संस्थाओं के माध्यम से खादी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने तथा उसे विकसित करने का रहा है। इस दिशा में समय समय पर कई उपाय किये हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं :—

(1) खादी उद्योगों के प्रोत्साहन तथा पोषण के लिए सस्ती, सुगम तथा व्यापक सहायता की व्यवस्था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समाज के कमजोर तथा असुरक्षित वर्गों को लाभ पहुंचे।

(2) गुणवत्ता तथा मात्रा की दृष्टि से सूती खादी का उत्पादन बढ़ाने के लिए उच्च गति के छः तकुओं वाले नये माडल चर्खे और ग्राम लक्ष्मी कर्घे शुरू करना।

(3) डी.आर.डी.ए. के सक्रिय सहयोग से गहन खादी उत्पादन तथा रोजगार सृजन योजना देश के भिन्न-भिन्न भागों में शुरू की गई है।

(4) कातने वालों को नियमित तथा बढ़िया कच्चा माल सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सिल्वर संयंत्र स्थापित करना।

(5) चरखों के बेकार पड़े रहने से बचने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में नये मॉडल के चरखों हेतु स्पेयर पार्ट के भण्डारण एवं आपूर्ति हेतु सुविधाओं का विस्तार करना।

(6) के.वी.आई. उत्पादों के लिये मार्ग प्रशस्त करने के लिए नाबार्ड और सिडबी की वित्तीय सहायता से नये खादी भण्डार/भवन स्थापित करना ताकि उत्पाद उपभोक्ता के घरों तक पहुंच सके।

(7) नयी संस्थाओं को सूचीबद्ध करने के लिए प्रक्रियाओं का सरलीकरण करना, रुग्ण तथा समस्याग्रस्त संस्थाओं को पुनः चालू करना और सक्रिय समन्वय हेतु राज्य स्तरीय सघों का गठन करना आदि।

इसके अलावा, आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, खादी उत्पाद विकास केन्द्रों, परिधान उत्पादन केन्द्रों तथा खादी निर्यातोन्मुख एककों का विकास शुरू करने का प्रस्ताव है।

इन योजनाओं के 8वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कार्यान्वित किये जाने की आशा है।

भारी उद्योग विभाग के प्रबंधाधीन उपक्रम

1557. **श्री वीरेन जे० शाह :**
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार, भारी उद्योग विभाग द्वारा कुल कितने उपक्रमों का प्रबन्ध किया जा रहा है ;

(ख) इन उपक्रमों में सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि का निवेश किया गया है और कितनी धनराशि पर सरकार को ब्याज देना पड़ता है ;

(ग) वार्षिक ब्याज के रूप में कुल कितनी धनराशि का भुगतान करना पड़ता है; और

(घ) इन सभी उपक्रमों द्वारा अर्जित किये जा रहे वार्षिक लाभ का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग और लोक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) भारी उद्योग विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में सरकारी क्षेत्र के 53 उपक्रम है।

(ख) सरकार ने इन उपक्रमों में कुल 2130.55 करोड़ रुपये की धनराशि निवेश की है। तथापि, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लिए गए पुर्जों पर सरकार द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जाता है।

(ग) विवरण I पर संलग्न है (**नीचे देखिये**)।

(घ) विवरण II पर संलग्न है (**नीचे देखिए**)।

विवरण–I

(रुपए हजारों में)

क्रम सं०	उपक्रमों का नाम	वास्तविक 1990-91	वास्तविक 1991–92 (अनंतिम)
1.	एण्ड्यू यूल एण्ड कं० लि०	14,99	11,62
2.	भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स लि०	6,01,43	5,05,00
3.	भारत भारी उद्योग निगम लि०	—	11,59
4.	भारत हेवी प्लेटस एण्ड वेसलस लि०	2,49,45	—
5.	ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी लि०	—	—
6.	भारत यंत्र निगम लि०	—	17,07
7.	बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लि०	5,56,98	—
8.	भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कं० लि०	12,78	56,81
9.	सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लि०	—	12,50,00
10.	हिन्दुस्तान कैबल्स लि०	5,73,67	77,05
11.	हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैन्यूफैक्चरिंग कं० लि०	59,83	30,65
12.	हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि०	2,24,97	10,46
13.	इन्स्ट्रूमेंटेशन लि०	87,52	88,47
14.	लगन जूट मशीन कं० लि०	59	45
15.	मारुति उद्योग लि०	9,11,55	7,09,69
16.	नेपा मिल्स लि०	5,48,18	2,87,89
17.	प्रागटूल्स लिमिटेड	—	95,00
18.	नेशनल इंडस्ट्रियल्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लि०	—	2.94
19.	तुगभद्रा स्टील प्रोडक्टस लि०	87,19	56,19
20.	टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लि०	—	88,50
21.	हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि०	20,00,00	—
	कुल :	59,29,13	32,99,38

विवरण-II

(लाख रुपये में)

क्र०सं०	सरकारी क्षेत्र का उपक्रम	1989-90 (वास्तविक)	1990-91 (वास्तविक)	1991-92 (वास्तविक) (अन्तिम)
1	2	3	4	5
1.	एण्ड्रयू यूल एण्ड कं० लि०	1008	1100	845
2.	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि०	21319	20146	21300
3.	भारत हैवी कैमिकल्स एंड फैसन्स लि०	251	304	126
4.	भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजी० लि०	-692	-837	-865
5.	बेबर्ड इंडिया लिमिटेड	-100	-137	-134
6.	भारत पम्पस एंड कम्प्रेसर्स लि०	-809	-296	-321
7.	भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कं० लि०	3	79	378
8.	ब्रैथवेट एंड कंपनी लि०	-567	-539	-250
9.	बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड	-598	-344	-748
10.	भारत वैक्स एंड वाल्वस लिमिटेड	-226	-195	-116
11.	बेरोल बर्न लिमिटेड	-129	-119	-90
12.	साइकिल कारपोरेशन आफ इंडिया लि०	-3071	-3016	-1300
13.	नेशनल साइमोइकिल कारपोरेशन आफ इंडिया लि०	-1011	-1820	-1166
14.	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि०	-3362	-9951	-14396
15.	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड	791	232	-1499
16.	एच०एम०टी० लिमिटेड	581	1558	1620
17.	एच० एम० टी० बियरिंग लि०	21	158	293
18.	इन्स्ट्रूमेंटेशन लि०	211	14	-450
19.	राजस्थान इलैक्ट्रोनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटस लि०	64	68	39
20.	जैसप एंड कंपनी लि०	135	-138	-280
21.	लयन जूट मशीनरी कंपनी लि०	20	28	45
22.	मारुति उद्योग लि०	5005	4816	3500
23.	माइनिंग एंड अलाइड मशीन कारपो० लि०	-1529	-3769	-3466
24.	नेशनल इन्स्ट्रूमेंटस लिमिटेड	-535	-818	-798
25.	प्रागा टूल्स लिमिटेड	83	-170	-242
26.	रिचर्डसन एंड क्रुडास लि०	-777	-864	-1232
27.	स्कूटर्स इंडिया लि०	-4289	-4825	-5250
28.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि०	-442	-361	-1036
29.	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्टस लि०	21	47	62
30.	सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लि०	-6288	-2933	252

1	2	3	4	5
31.	हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि०	−5584	−6137	−7132
32.	हिन्दुस्तान न्यूजप्रिन्ट लि०	2036	3102	3765
33.	माण्डया नेशनल० पेपर मिल्स लि०	−648	−571	−1035
34.	नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लि०	−2333	−2054	−2214
35.	नेपा लिमिटेड	−426	618	14
36.	भारत आपथैल्मिक लि०	−864	−1040	−1122
37.	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मै० न्यू० कं० लि०	797	198	250
38.	हिन्दुस्तान साल्टस लि०	−18	−10	30
39.	सांभर साल्टस लि०	5	71	53
40.	टैनरी एंड फुटवीयर कारपोरेशन आफ इंडिया लि०	−1616	−1870	−1956
41.	टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लि०	−1195	−1418	−1578
42.	रिहैबलिटेशन इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लि०	−1942	−2712	−2803
43.	भारत लैदर कारपोरेशन	−77	−129	−85
44.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि०	−10432	−5387	−6274
45.	नेशनल इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि०	7	16	16
46.	हुगली प्रीटिंग कंपनी लि०	−16	−7	−3
47.	ब्रेथवेट, बर्न, जेसप कन्स्ट्रक्शन कंपनी लि०	13	72	404
48.	ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी लि०	72	79	163
49.	एच. एम. टी. (इंटरनेशनल) लि०	281	349	93
50.	भारत भारी उद्योग निगम लि०	) नियंत्रक कंपनियां होने के कारण इनके निर्माणकारी कार्यकलाप नहीं है ।		
51.	भारत यंत्र निगम लि०	)		
52.	दामोदर सीमेंट एण्ड स्लेग लि०	) वाणिज्यिक कार्यकलाप शुरू नहीं किए		
53.	स्कूटर्स इंडिया (इन्टरनेशनल) जी एम बी एच जर्मनी	)		

Hike in news print prices

1558. SHRI CHIMANBHAI MEHTA:.
SHRI SOM PAL:
SHRI SARADA MOHANTY;
SHRIMATI MIRA DAS:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a)-whether it[1] is a fact that the newsprint prices have been hiked five times during the last three years from May, 1989 to May, 1992;

(b) whether it is a fact that these hikes have resulted in 60 to 95 per cent price rise and mostly the burdlen has been passed over to newspaper readers;

(c) whether it is a fact that news print manufacturing industry is largely located, in the public sector; if so, the authority responsible for mal-functioning of the industry;